The dues have accumulated over a period of time because of wide gap between the value of coal supplied by coal companies and payments made by the power utilities.

(d) One of the main reasons for non-clearance of coal bills is the financial constraints faced by the power utilities. Following are the important steps taken to recover the outstanding dues :

(i) All power units commissioned after 1-4-89 were being supplied coal only against advance payments or against revolving Letter of Credit.

(ii) Government of India have decided to adjust all undisputed coal sales outstanding as on 31-5-1990 against the Central Assistance to State Plans payable to the State Governments whose State Electricity Boards and Power Utilities had defaulted, in four equal instalments.

(iii) As a result of mounting arrears of outstanding dues, Ministry of Coal advised CIL to start supplying coal to the Power Utilities only against advance payments. This scheme which is better known as Cash and Carry Scheme was introduced with effect from 1-10-1991.

(iv) State Government have been requested to pursuade/enable their State Electricity Boards to clear the outstanding dues at the earlist.

मंत्रालय के साथ सांसदों का पत्र-व्यवहार

286. **श्री मोहम्मद अफजल** उर्फ **मीम अफजल** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1990 से 31 मार्च, 1993 की अवधि के दौरान सांसदों द्वारा मंत्रालय को कितने पत्र लिखे गए और उनका क्रमवार वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितने पत्रों की पावती भेजी गई ;

(ग) कितने पत्रों के अन्तिम उत्तर भेजे गए; और

(घ) मंत्रालय द्वारा भेजे गए क्रमशः सकारात्मक और नकारात्मक उत्तर वाले अंतिम पत्रों के पृथक-पृथक आंकड़े क्या हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (घ) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मेघालय को रॉयल्टी के रूप में दी गई धनराशि

287. **श्री शिव चरण सिंह** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में कोयले के कुल कितने भंडार हैं और कोयले की वार्षिक आवश्यकता कितनी है तथा देश में इसका वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) देश में कोयले के उत्पादन तथा इसकी आवश्यकता के बीच कितना अंतर है और विदेशों से आयातित कोयले की मात्रा तथा उसकी दर का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मेघालय को रॉयल्टी के रूप में कोई धनराशि दी गई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त रायल्टी की धनराशि कितनी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) (क) और (ख) भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा किए

गए सर्वेक्षण के अनुसार 1-1-1993 की स्थिति के अनुसार कोयले का अनुमानित भण्डार (1200 मीटर तक की गहराई में) 4193.7 बिलियन टन है।

वर्ष 1992-93 के दौरान देश में सभी उपभोक्ता क्षेत्रों की कोयले की कुल मांग की तुलना में वास्तविक आपूर्ति तथा वास्तविक उत्पादन नीचे दर्शाया गया है :

(मिलियन टन में)

मूल्यांकित मांग	वास्तविक आपूर्ति	उत्पादन	टिप्पणी
258.10 (5.30)	241.00 (2.47)	238.23 (अनन्तिम)	कोष्टक में दिए गए आंकड़े वांछनीय मिडलिंग्स दर्शाते हैं।

मूल्यांकित मांग व्युत्पन्न स्वरूप की है। कुल मिलाकर देशी कोयले का उपादन 1992-93 के दौरान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त था, केवल एकीकृत इस्पात संयंत्रों को छोड़कर जो कि देशीय उपलब्धता तथा मांग के बीच अन्तराल को पूरा करने के लिए देशी कोयले के साथ मिश्रण करने तथा इस्पात संयंत्रों में प्रयुक्त किये जाने वाले कुल मिश्रण की गुणवत्ता में सुधार किए जाने के प्रयोजनार्थ निम्न राख कोकिंग कोयले का मुख्य आयातक है।

वर्ष 1992-93 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों नामतः भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० तथा विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा आयात किए गए कोयले की मात्रा तथा कीमत के संबंध में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(आंकड़े अनन्तिम)

आयात (मि० टन में)	आयात के देश	कीमत (करोड़ रुपए में)
5.908	आस्ट्रेलिया पोलैण्ड न्यूजीलैण्ड	1145.94

(ग) से (ङ) मेघालय में कोल इण्डिया लिमिटेड की कोई कोलियरी नहीं है। इसलिए, कोल इण्डिया लि० द्वारा मेघालय की राज्य सरकार को कोयले की रायल्टी का भुगतान किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

Requirement Coal for power sector in Gujarat

288. SHRI VITHALBHAI M. PATEL : Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) what is the annual requirement of coal for the power sector in Gujarat ;

(b) what is the quantity of coal actually supplied to the power houses of Gujarat during the last two years and up to 30th September, 1993 ;

(c) whether the required quantity of coal has been supplied to these power houses ;

(d) if not, the reasons therefor ; and

(e) what steps are being taken by Government to supply the required quantity of coal to these power stations ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA) : (a) The demand of coal for the power houses under Gujarat Electricity Board (GEB) for the year 1993-94, as assessed by Central Electricity Autho-